



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

ब्रिक्स एवं बहुध्रुवीयता : उभरते शक्ति गठबंधनों के दौर में भारत की प्रभावकारी भूमिका

डॉ० शिल्पी जायसवाल*

*असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, नीतीश्वर महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।
सम्बद्ध इकाई बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार।

Abstract : पिछले दो दशकों में ब्रिक्स (BRICS) एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजरा है। प्रारम्भ में उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक सहयोग के मंच के रूप में स्थापित यह संगठन आज वैश्विक दक्षिण (Global South) की आकांक्षाओं, विकास संबंधी प्राथमिकताओं तथा अधिक न्यायसंगत वैश्विक शासन व्यवस्था की मांग का सशक्त प्रतिनिधि बनकर उभरा है। BRICS+ के विस्तार के पश्चात इसमें अब 11 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ— ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया, इंडोनेशिया तथा ईरान—शामिल हैं। ये देश सामूहिक रूप से विश्व की लगभग आधी जनसंख्या, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग एक-तिहाई तथा वैश्विक विनिर्माण उत्पादन के आधे से अधिक हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार BRICS केवल एक आर्थिक समूह नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति-संतुलन को प्रभावित करने वाला एक प्रभावशाली बहुपक्षीय मंच बन चुका है।

वर्ष 2026 में भारत की BRICS अध्यक्षता इस संगठन की सामूहिक क्षमता को विकासशील देशों के हित में ठोस परिणामों में परिवर्तित करने का एक ऐतिहासिक अवसर प्रदान करती है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में संरक्षणवादी व्यापार नीतियाँ, बढ़ते टैरिफ तथा व्यापारिक प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, जिनका सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में BRICS सदस्य देशों के मध्य व्यापारिक सहयोग को सुदृढ़ करना तथा इस सहयोग का विस्तार अन्य विकासशील देशों तक करना भारत की प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए। साथ ही, विकसित देशों द्वारा विनिर्माण गतिविधियों को पुनः अपने देशों में स्थापित करने (Reshoring of Manufacturing) की बढ़ती प्रवृत्ति वैश्विक उत्पादन संरचना में परिवर्तन ला रही है। इसके परिणामस्वरूप BRICS देशों के लिए आवश्यक हो गया है कि वे अपनी औद्योगिक एवं विनिर्माण नीतियों में समन्वय स्थापित कर उत्पादन क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मकता तथा आर्थिक लचीलेपन (Economic Resilience) को सुदृढ़ करें।

मुख्य शब्द : BRICS+, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, दक्षिण सहयोग, G-20।

विषय प्रवेश :

BRICS पाँच उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन व दक्षिण अफ्रीका से बना समूह है। विश्व के शक्ति परिवर्तन के केन्द्र के रूप में इस समूह की स्थापना हुई।¹ रूस के विदेश मंत्रालय में सन् 1996 व 1998 के दौरान BRICS की अवधारणा की नींव पड़ी। तत्कालीन रूसी विदेश मंत्री येवगेनी प्रिमाकोव ने रूस, भारत व चीन से बने एक रणनीतिक यूरोशियन त्रिकोण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसका उद्देश्य पश्चिमी देशों की निर्भरता से हटकर रूस की विदेश

नीति में विविधता लाना था। रूस व चीन ने अप्रैल 1997 में “बहुध्रुवीय विश्व” व ‘नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना’ की संयुक्त घोषणा को अपनाया।²

BRICS शब्द को मूल रूप से गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री ‘जिम ओ’ निल द्वारा सन् 2001 में एक शोध पत्र में गढ़ा गया, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि उस समय के ‘BRIC’ देश (ब्राजील, रूस, भारत व चीन) G-7 अमीर अर्थव्यवस्थाओं को चुनौती देने हेतु तैयार थे। BRICS की स्थापना जून 2006 में हुई थी। प्रारम्भ में ब्राजील, रूस, भारत व चीन (BRIC) में सम्मिलित थे, वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इस समूह में सम्मिलित हुआ, जिसके परिणामतः इस संगठन का नाम BRIC से परिवर्तित होकर BRICS हो गया।³

BRICS समूह का विस्तार करते हुये 1 जनवरी 2024 में इसमें चार नये सदस्य देशों—मिस्र, इथियोपिया, ईरान व संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आधिकारिक रूप से सम्मिलित किया गया। 1 जनवरी, 2025 में इंडोनेशिया भी इस BRICS संगठन में सम्मिलित हुआ।⁴

BRICS के 2024 के शिखर सम्मेलन में ‘साझेदार देशों’ की एक श्रेणी को भी प्रारम्भ किया गया। बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाइलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान इन श्रेणी में सम्मिलित होने वाले पहले देश थे। पूर्ण सदस्य का दर्जा न प्राप्त होने के बावजूद ‘साझेदार देशों’ की श्रेणी में सम्मिलित होने से ये सभी देश BRICS शिखर सम्मेलनों में प्रतिभाग कर सकते हैं।⁵

BRICS की आवश्यकता :

BRICS की आवश्यकता एक संतुलित वैश्विक विकास को बढ़ावा देने एवं अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लेने में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के प्रभुत्व को कम करने के उद्देश्य से एक साझा लक्ष्य से उत्पन्न हुई। BRICS के सदस्य राष्ट्र— ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका— ये सभी देश विश्व के विकासशील व तेजी से अग्रसर होने वाली अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं व इनका उद्देश्य एक समतापूर्ण विश्वव्यवस्था स्थापित करना है। BRICS समूह निर्धनता, असमानता एवं जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करते हुये व्यापार, वित्त, प्रौद्योगिकी एवं सतत विकास में सहयोग में वृद्धि करने हेतु एक वैश्विक मंच प्रदान करता है।⁶

BRICS का उद्देश्य :

BRICS समूह एक बहुपक्षीय मंच है जिसके अन्तर्गत विश्व की पाँच उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएँ सम्मिलित है जिसमें विश्व की जनसंख्या का 41 प्रतिशत, वैश्विक GDP का लगभग 24 प्रतिशत व विश्व व्यापार का 16 प्रतिशत भाग सम्मिलित है। BRICS सम्मेलनों में क्षेत्रीय मुद्दों के साथ ही वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होती है। BRICS का उद्देश्य अलग-अलग क्षेत्रों में सदस्य राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक लाभकारी सहयोग में वृद्धि करना है। इसके साथ ही BRICS समुदाय में जलवायु परिवर्तन, आर्थिक संकट, ऊर्जा, आतंकवाद, विश्व व्यापार इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण एवं ज्वलंत मुद्दों पर भी चर्चा होती है।⁷

ब्रिक्स की संरचना एवं कार्य :

BRICS का कोई स्थायी सचिवालय या औपचारिक संविधान नहीं है। BRICS वार्षिक शिखर सम्मेलनां, मंत्रिस्तरीय बैठकों एवं विभिन्न कार्य समूहों की प्रणाली के माध्यम से संचालित होता है। BRICS की अध्यक्षता प्रत्येक वर्ष इसके सदस्यों के मध्य बारी-बारी से जाती है, जिससे प्रत्येक वर्ष का एंजेडा निर्धारित किया जा सके। BRICS समूह द्वारा कई ऐसे पहलुओं का प्रारम्भ किया गया जो कि सदस्य देशों को विकास, व्यापार, ऊर्जा, वित्त एवं डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्रों का सहयोग करने में सहायता करती है। इन सभी प्रयासों से समावेशी वैश्विक व्यापार को आकार देने में BRICS की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाती है। इसकी संरचना निम्नलिखित है—

1. New Development Bank (NDB) :

BRICS देशों द्वारा NDB (New Development Bank) की स्थापना 2014 में हुई जो कि BRICS की सबसे महत्वपूर्ण संस्थागत उपलब्धि है। इसका मुख्यालय चीन के शंघाई में स्थित है, इसका उद्देश्य विश्व बैंक एवं IMF जैसे वैश्विक वित्तीय संस्थाओं के विकल्प के रूप में कार्य करना है।

NDB के प्रमुख कार्य :

1. बुनियादी ढाँचों एवं विकास परियोजना हेतु वित्तपोषित।
2. स्थानीय मुद्राओं में ऋण प्रदान करना।
3. स्वच्छ ऊर्जा, शहरी विकास व डिजिटल बुनियादी ढाँचों का समर्थन।

NDB के महत्वपूर्ण प्रभाव :

120 से अधिक परियोजनाओं हेतु 40 अरब डॉलर से अधिक की राशि स्वीकृत की गयी। इसके साथ ही भारत को 6.9 अरब डॉलर की परियोजनाएँ प्राप्त हुई। इसके वित्त पोषित प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं—

1. स्थायी ऊर्जा
2. मेट्रो रेल प्रणाली
3. सड़क एवं परिवहन
4. जल एवं स्वच्छता।

भारत के लिए महत्व :

भारत में सड़क, मेट्रो, अक्षय ऊर्जा, जल संरक्षण एवं अन्य आधारभूत परियोजनाओं हेतु NDB द्वारा वित्त सहायता प्रदान की गई है इससे भारत के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने में मदद मिलती है।

2. Contingent Reserve Arrangement : (CRA) आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था :

इसकी स्थापना 2014 में हुई व इसका प्रारंभिक कोष—100 अरब अमेरिकी डॉलर है। CRA एक वित्तीय सुरक्षा तंत्र है जिसका उद्देश्य सदस्य देशों को भुगतान संतुलन (Balance of Payment) संकट या विदेशी मुद्रा की अस्थायी कमी की स्थिति में सहायता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य निम्न है—

- तत्कालीन सहायता प्रदान करना।
- वैश्विक वित्तीय अस्थिरता से सुरक्षा।
- वित्तीय संकट के दौरान सदस्य देशों को तरलता उपलब्ध कराना।
- यह सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मुद्रा अस्थिरता से बचाता है।
- IMF पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना।

CRA का महत्व :

1. वित्तीय संकट के दौरान सदस्य देशों के मध्य सहयोग में वृद्धि है।
2. वैश्विक आर्थिक आपदा से निपटने की क्षमता को मजबूत करता है।
3. BRICS देशों के समूह को आर्थिक स्थिरता में वृद्धि।

3. BRICS Business Council :

2013 में डरबन शिखर सम्मेलन (दक्षिण अफ्रीका) में इसकी स्थापना का निर्णय लिया गया। BRICS बिजनेस काउंसिल की स्थापना सदस्य देशों के निजी क्षेत्र के मध्य व्यापार, निवेश एवं औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया इसका प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है—

1. व्यापार एवं निवेश को प्रोत्साहित करना।
2. उद्योगपतियों एवं निवेशकों के मध्य सहयोग में वृद्धि।
3. कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, विनिर्माण एवं तकनीकी क्षेत्रों में साझेदारी विकसित करना।
4. लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को अवसर उपलब्ध कराना।
5. नवाचार, डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं स्टार्टअप सहयोग को बढ़ावा देना।

भारत के लिये महत्व :

ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल का भारत हेतु यह महत्व है कि इसके माध्यम से भारत के उद्योगों MSMEs, स्टार्टअप एवं निर्यातकों को BRICS देशों के विशाल बाजार तक पहुँच तथा निवेश आकर्षित करने एवं तकनीकी सहयोग प्राप्त करने के नये अवसर प्राप्त होते हैं।⁸

BRICS एवं भारत :

वर्तमान समय में ब्रिक्स विश्व की सबसे प्रभावशाली बहुपक्षीय संस्थाओं में से एक है। यह संगठन वैश्विक आर्थिक सहयोग, विकास, निवेश, वित्तीय स्थिरता एवं बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था (Multipolar World Order) को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा। भारत BRICS का संस्थापक सदस्य देश है व इसकी नीतियों एवं निर्णयों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका का सम्पादन करता है। 'Global South' की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में BRICS भारत के लिये महत्वपूर्ण माध्यम है।⁹

इस समूह का सदस्य होने के कारण ब्रिक्स में भारत की भूमिका विशेषतः इस संस्था के निर्माण में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उल्लेखनीय है कि BRICS के बैंक NDB की स्थापना का प्रस्ताव मार्च 2012 के नई दिल्ली में भारत द्वारा 4वें शिखर सम्मेलन में किया गया। इसके पीछे भारत का मुख्य उद्देश्य यह था कि मुख्य रूप से BRICS देशों द्वारा वित्तपोषित एवं प्रबंधित किये जाने एवं BRICS के नेतृत्व वाली दक्षिण-दक्षिण विकास बैंक की स्थापना किया जाये जिसके आधार पर विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे एवं सततशील विकास परियोजनाओं में उपयोग किया जा सके।¹⁰

वैकल्पिक वित्तीय संरचना :

BRICS संगठन भारत को IMF एवं विश्व बैंक (World Bank) जैसे पश्चिमी प्रभुत्व वाले संस्थानों के बाहर वित्तीय संस्थानों तक पहुँच प्रदान करता है। BRICS की संस्था NDB ने भारत के 28 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं हेतु लगभग 10 बिलियन अमरीकी डालर के ऋण को स्वीकार किया, जिसमें चेन्नई, इंदौर एवं मुंबई मेट्रो सिस्टम, दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एवं नमो भारत हाईस्पीड ट्रेने सम्मिलित है।

प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल सहयोग :

BRICS AI, फिनटेक, 5G एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकीयों में सहयोग को बढ़ावा देता है जिससे वैकल्पिक परिस्थितिक तंत्र निर्मित होते हैं। भारत की स्मार्ट परियोजनाओं हेतु NDB का समर्थन यह भी प्रदर्शित करता है कि ब्रिक्स किस प्रकार डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ करता है एवं भारत को बाह्य प्रौद्योगिकी प्रेरित झटकों से बचाव प्रदान करता है।¹¹

रणनीतिक एवं सुरक्षा सहयोग :

भारत के लिये BRICS एक ऐसा महत्वपूर्ण मंच है जिसके माध्यम से भारत सुरक्षा, साइबर चुनौती, आतंकवाद विरोधी उपायों एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के समाधान पर बात करता है। BRICS समूह किसी सैन्य गठबंधन के रूप में कार्य नहीं करता वरन् आपसी विश्वास की वृद्धि में रणनीतिक सहयोग प्रदान करता है। इसका उदाहरण सन् 2025 में पहलगाम आतंकी हमले की एकजुट निंदा करना था, जिसने आतंकवाद के विरुद्ध सामूहिक रुख को चिन्हित किया। भू-राजनीतिक तनावों के पश्चात् भी भारत, रूस एवं चीन जैसी प्रमुख शक्तियों के साथ अपने संबंधों में संतुलन बनाये रखने हेतु BRICS संगठन का प्रयोग करता है ये BRICS देश सीक्रेट जानकारी आपस में साझा कर सकते हैं, क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं पर विमर्श कर सकते हैं एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के नियमित परामर्श के माध्यम से उभरते चुनौतियों एवं खतरों के लिये समन्वित प्रतिक्रियाएँ तैयार कर सकते हैं।¹²

भारत की विदेश नीति में BRICS का महत्व :

भारत की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा, वैश्विक शांति, आर्थिक विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति का एक माध्यम BRICS बन चुका है भारत 'वसुधैव कुटुम्बकम्' एवं 'सबका साथ सबका विकास' जैसे अवधारणाओं के अनुरूप BRICS में समावेशी विकास एवं दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-South Cooperation) को प्रोत्साहन देता है। भारत की इस सन्दर्भ में सक्रिय भूमिका यह रही है कि वैश्विक दक्षिण के विकासशील देशों की समस्या BRICS के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मंच तक प्रभावी रूप से पहुँचे। भारत की विदेश नीति Multi-Alignment अथवा संरेखण पर आधारित है, जिसके अन्तर्गत भारत, अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान, आसियन एवं BRICS जैसे विभिन्न मंचों के साथ संतुलित संबंध बनाये रखता है। BRICS भारत को रूस या चीन जैसे देशों के साथ संवाद बनाये रखने हेतु अवसर देता है जिससे क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्थिरता को बढ़ावा मिले। BRICS भारत को अपने कूटनीतिक संवाद के दायरे को विस्तृत करने, एशिया में पश्चिमी देशों के प्रभाव का संतुलन स्थापित करने एवं अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाये रखने में सहायता करता है। इसके साथ ही भारत BRICS के भीतर चीन के अत्यधिक आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभाव के सन्दर्भ में अपने लिये एक संतुलित स्थान बनाने का प्रयास कर रहा है। भारत BRICS समूह के भीतर आपसी सहमति स्थापित करने, साझा हितों को बढ़ावा देने व समान मूल्यों को प्रोत्साहित करने की बेहतर स्थिति में है और यही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है।

BRICS के सदस्य देश विश्व की 45 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं एवं वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 36 प्रतिशत का योगदान देते हैं। इस कारण BRICS वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक अत्यन्त प्रभावशाली मंच बन चुका है। BRICS के विस्तार का प्रस्ताव मुख्य रूप से चीन एवं रूस द्वारा आगे बढ़ाया गया। इसके पीछे का मुख्य तर्क यह था कि नए सदस्य देशों को सम्मिलित करने से यह मंच विकासशील देशों का अधिक प्रतिनिधि संगठन बनेगा तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके हितों एवं समस्याओं को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकेगा। BRICS के सदस्य देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था (International Financial Architecture) के संबंध में व्यापक सहमति देखने को मिलती है। यह मंच वैश्विक वित्तीय प्रणाली के वैकल्पिक ढाँचे को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। इसके अन्तर्गत सदस्य देशों के मध्य व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग का बढ़ावा देने एवं नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समर्थन करना है। नए देशों का सम्मिलित होना इन उद्देश्यों को और भी अधिक सशक्त बनाता है।

इसके बावजूद भारत एवं ब्राजील ने BRICS के विस्तार की प्रक्रिया को लेकर कुछ सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। भारत द्वारा नए सदस्य देशों के प्रवेश के संदर्भ में कुछ कठोर मानदंड निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। इसमें प्रमुख शर्त यह रही है कि कोई भी नया सदस्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के अधीन न हो। यदि यह शर्त लागू होती है, तो ईरान जैसे देशों का BRICS में प्रवेश कठिन हो जाता। यहाँ पर भारत का दोहरा उद्देश्य था—

1. यह सुनिश्चित करना कि नये सदस्यों का चयन केवल संस्थापक देशों के प्रभाव के आधार पर न हो वरन् पारदर्शी एवं नियम-आधारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाये।
2. ऐसे देशों के प्रवेश से बचना जो कि अत्यधिक अमेरिकन विरोधी नीति को अपनाते हों क्योंकि इससे BRICS के अंदर चीन की रणनीतिक एवं राजनीतिक भूमिका और भी अधिक प्रभावशाली हो सकती है।¹³

भारत की अध्यक्षता में BRICS 2026 सम्मेलन

वर्ष 2026 के लिये अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनावी सहायता संस्थान (अंतर्राष्ट्रीय IDEA) की अध्यक्षता तथा G-20 जैसी प्रभावशाली संस्था की अध्यक्षता, इन सभी के अन्तर्गत भारत पिछले एक दशक से वैश्विक स्तर पर अपनी एक प्रभावशाली भूमिका का सम्पादन किया है। इस सन्दर्भ में एक नई उपलब्धि भारत के लिये यह है कि भारत वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करने वाला है विश्व की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रिक्स का वैश्विक GDP में में करीब 40 प्रतिशत का योगदान है। भारत की अध्यक्षता में वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली BRICS का थीम— 'लचीलापन, नवाचार, सहयोग एवं विकास के लिये निर्माण' (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability) रखा गया है।

BRICS के चार प्रमुख स्तंभ :

लचीलापन — वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, स्वास्थ्य और जलवायु जोखिमों से निपटने की क्षमता को मजबूत करना।

नवाचार — सेवा वितरण और विकास के लिये DPI, फिनटेक, AI और ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देना।

सहयोग — नीति, वित्त, व्यापार, शासन सुधार और जनभागीदारी में BRICS देशों के बीच समन्वय को मजबूत करना।

सततता — जलवायु कार्यवाही, हरित वित्त, ऊर्जा संक्रमण और सतत विकास को गति देना।

BRICS 2026 की आधिकारिक वेबसाइट btovd2026.gov.in को विदेश मंत्री डॉ० एस० जयशंकर ने 13 जनवरी को आधिकारिक रूप से लान्च किया। साथ ही विदेश मंत्री ने यह कहा कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से प्रेरित होकर 'मानवता प्रथम' एवं 'जन-केन्द्रित' दृष्टिकोण के साथ अध्यक्षता कर रहा।¹⁴

उल्लेखनीय है कि इस बार 2026 में भारत चौथी बार BRICS की अध्यक्षता कर रहा, इसके पूर्व उसने वर्ष 2012, 2016, 2021 में अध्यक्षता कर चुका है।¹⁵

इस बार BRICS के सम्मेलन में ग्लोबल साउथ की आवाज को और भी अधिक मजबूती से रखने की बात होगी, साथ ही आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, AI इनोवेशन इत्यादि जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। सम्मेलन में इस बार का विषय यह प्रदर्शित करता है कि 'BRICS' सदस्यों के मध्य सहयोग, साझा चुनौतियों का संतुलित एवं समावेशी तरीके से समाधान करने में सहायता कर सकता है।¹⁶

BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक : 15 मई, 2026

BRICS देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 14 एवं 15 मई 2026 को नई दिल्ली, भारत में हुई। इसके अंतर्गत प्रमुख वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

मंत्रियों ने 'लचीलापन, नवाचार, सहयोग एवं स्थिरता के लिये निर्माण' Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability विषय के तहत 2026 में भारत की BRICS की अध्यक्षता हेतु पूर्ण समर्थन प्रदान किया। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद, बहुध्रुवीयता को मजबूत करने तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने हेतु अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) के महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया जिससे संप्रभु राज्य शांति एवं सुरक्षा बनाये रखने, सतत विकास को बढ़ाने, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने व उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु सहयोग पर बल दिया जिसका उद्देश्य पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हेतु एक उज्ज्वल साझा भविष्य का निर्माण करना है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के सन्दर्भ में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों एवं सिद्धान्तों को क्रियान्वित करना, जिससे अंतर्गत सशस्त्र संघर्षों के रोकथाम, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों, मध्यस्थता एवं शांति प्रक्रिया पर सहयोग के माध्यम से अपनी सहमति प्रदान किया है। इसके साथ ही मंत्रियों ने G-20 की प्रमुख भूमिका पर जोर दिया जो कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु एक वैश्विक मंच है एवं यह उभरती तथा विकसित अर्थव्यवस्थाओं को समाज एवं पारस्परिक रूप से लाभकारी आधार पर संवाद करने हेतु एक मंच प्रदान करता है। इसके साथ मंत्रियों ने महिला, शांति एवं सुरक्षा (WPS) एजेंडा के पूर्ण कार्यान्वयन एवं उन्नति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। मंत्रियों ने जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना करने हेतु पेरिस समझौते के उद्देश्य एवं लक्ष्यों तथा संयुक्त वित्तीय परिषद् (UNFCCC) के उद्देश्यों की प्राप्ति में एकजुट रहने का संकल्प लिया।

BRICS देशों के विदेश मंत्रियों ने यह स्वीकार किया कि AI संसाधनों की सुलभता को बढ़ाने के साथ ही उनकी सुरक्षा, समावेशिता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने, AI प्रणालियों की ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने, AI विज्ञान तथा नवाचार को प्रोत्साहित करने, विश्वसनीय AI प्रौद्योगिकीयों को विकसित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सभी देशों द्वारा विशेषतः वैश्विक दक्षिण के देशों के न्यायपूर्ण निष्पक्ष, समान तथा समृद्ध भविष्य को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक होगा। इन सभी ने फरवरी 2026 में AI Impact Submit के सफल आयोजन पर भारत को बधाई दी। साथ ही शंघाई में आयोजित विश्व AI सम्मेलन और वैश्विक AI शासन पर उच्च स्तरीय बैठक व AI अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने में सभी के योगदान को भी स्वीकार किया।¹⁷ भारत इन सम्मेलन से स्वयं को स्वतंत्र तथा वैश्विक शक्ति के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। भारत की विशेषता यह है कि उसके संबंध विश्व की सभी शक्तियों के साथ अत्यन्त मजबूत है। अमेरिका के साथ जहाँ भारत की स्थिति प्रभावशाली है तो वही दूसरी ओर रूस भी भारत की विदेश नीति में प्रभावशाली भूमिका निभा रहा।

BRICS 2026 का सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा जबकि वैश्विक राजनीति अत्यन्त विषम परिस्थिति में है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अत्यन्त तनाव के माहौल में है। भारत का चीन के साथ संबंध तनावपूर्ण स्थिति में है फिर भी भारत का चीन के साथ संवाद बनाने की कोशिश जारी है जोकि 2020 में गलवान घाटी में हुये हिंसक घटना से संबंध तनाव की स्थिति में रहा।

भारत का परिवर्तित लक्ष्य :

BRICS समूह उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के मध्य सहयोग को प्रोत्साहित करने हेतु निर्मित हुआ था। किंतु धीरे-धीरे यह राजनीतिक रूप में परिवर्तित होता जा रहा। सऊदी अरब, ईरान, इथियोपिया, इजिप्ट एवं UAE जैसे देश BRICS में सम्मिलित हुये, जिनकी राजनीति व्यवस्था की महत्त्वकांक्षायें बिल्कुल अलग-अलग हैं। भारत की यह मंशा बिल्कुल भी नहीं है कि BRICS पश्चिमी देश के विरुद्ध एक संगठन के रूप में रहे जैसा कि चीन एवं रूस की कोशिश रही है।¹⁸

भारत इस सम्मेलन के माध्यम से यह चाहेगा कि सम्मेलन में विकास, वित्त, तकनीक के आदान-प्रदान पर वार्ता हो साथ ही चीन व रूस डॉलर की निर्भरता को कम करने व पश्चिमी

देशों के प्रभुत्व को चुनौती देने वाले मुद्दों पर भी सम्मेलन में वार्ता करेगा। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अमेरीका जैसे पश्चिमी देशों का प्रभाव घटने से भारत का वैश्विक मंच पर प्रभावशीलता बढ़ रही क्योंकि वह एक साथ कई बड़े देशों एवं समूह के साथ संबंध बनाये रखने में सक्षम है।¹⁹

नीतिगत सिफारिशें एवं आगे की राह (Policy Recommendations and Way Forward) :

वर्ष 2026 में भारत की BRICS अध्यक्षता इस समूह की सामूहिक शक्ति और क्षमता को वैश्विक दक्षिण (Global South) के विकासात्मक हितों के अनुरूप ठोस एवं व्यावहारिक परिणामों में परिवर्तित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में संरक्षणवादी व्यापार नीतियों, बढ़ते टैरिफ अवरोधों तथा व्यापारिक प्रतिबंधों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जिसका सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ा है। ऐसी परिस्थितियों में BRICS सदस्य देशों के मध्य आंतरिक व्यापार (Intra & BRICS Trade) को सुदृढ़ करना तथा इस सहयोग का विस्तार अन्य विकासशील देशों तक करना भारत की प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए।

भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (Digital Public Infrastructure) से संबंधित नवाचार जैसे आधार (Aadhaar), यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) तथा डिजीलॉकर (Digi Locker)—डिजिटल शासन, वित्तीय समावेशन तथा सार्वजनिक सेवा वितरण के क्षेत्र में विश्व स्तर पर प्रभावी और कम लागत वाले मॉडल के रूप में स्थापित हुई हैं। इन पहलों ने न केवल सरकारी सेवाओं की पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही को सुदृढ़ किया है, बल्कि नागरिकों की डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुँच को भी व्यापक बनाया है। विशेष रूप से UPI वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस तथा मॉरीशस सहित सात देशों में संचालित है, जो इसकी वैश्विक स्वीकार्यता तथा विस्तारशील क्षमता का प्रमाण है। भारत अपनी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से प्राप्त अनुभवों तथा तकनीकी विशेषज्ञता को BRICS+ सदस्य देशों एवं व्यापक वैश्विक दक्षिण (Global South) के साथ साझा कर उनकी डिजिटल परिवर्तन प्रक्रिया को गति प्रदान कर सकता है। साथ ही, तकनीकी सहयोग एवं क्षमता निर्माण के माध्यम से डिजिटल शासन, वित्तीय समावेशन, ई-गवर्नेंस तथा समावेशी आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। इन नीतिगत पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से वर्ष 2026 में भारत की BRICS अध्यक्षता वैश्विक दक्षिण की विकासात्मक प्राथमिकताओं को ठोस दिशा प्रदान कर सकती है। साथ ही, यह BRICS+ को एक ऐसे सशक्त, समावेशी और परिणामोन्मुख बहुपक्षीय मंच के रूप में स्थापित करने में सहायक होगी, जो व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करते हुए न्यायसंगत, संतुलित तथा बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। अतः भारत की BRICS अध्यक्षता केवल संगठन के प्रशासनिक नेतृत्व तक सीमित न रहकर, समावेशी विकास, आर्थिक सहयोग, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा सतत विकास को बढ़ावा देने वाली ठोस नीतिगत पहलों के माध्यम से BRICS को वैश्विक दक्षिण के हितों का एक प्रभावी और विश्वसनीय मंच बनाने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभा सकती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. https://icwa.in/show_content.php?lang=2&level=3&ls_id=4301 &lid= 3190. Accessed on 22/05/2026
2. bricscouncil.ru/en/history. Accessed on 26/05/2026
3. Gulpham, Shahanshah & Saeed, Ali. Dynamics of BRICS Nations: Challenges ahead. New Delhi : Paragon International Publishers, 2017.
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Member_states_of_BRICS Accessed on 31/05/2026
5. Council of foreign relations. [https://www.cfr.org/backgrounders/ what-brics-group-and-why-it-expanding](https://www.cfr.org/backgrounders/what-brics-group-and-why-it-expanding) Accessed on 03/06/2026
6. <https://testbook.com/hi/ias-preparation/brics> Accessed on 05/06/ 2026
7. <https://www.abplive.com/news/world/brics-virtual-summit-2022-what-is-brics-countries-reason-behind-it-motive-2152488> accessed on 07/06/2026
8. <https://testbook.com/hi/ugc-net-political-science/india-and-brics> Accessed on 10/06/2026
9. Harnessing BRICS for India's Strategic Ambitions Stable URL <https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/harnessing-brics-for-indias-strategic-ambitions> Accessed on 15/06/2026
10. Sharma, Arundhati. Indian Council of World affairs
Stable URL https://icwa.in/show_content.php?lang= 2&level= 3&ls_id=4301&lid=3190 access on 22/06/2026
11. Harnessing BRICS for India's Strategic Ambitions Stable URL <https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/harnessing-brics-for-indias-strategic-ambitions> Accessed on 03/07/2026
12. <https://testbook.com/hi/ugc-net-political-science/india-and-brics> Accessed on 10/07/2026
13. Paola Andrea Baroni, The Role of BRICS in India's Foreign Policy. Stable URL <https://www.e-ir.info/2024/12/12/the-role-of-brics-in-indias-foreign-policy/> Accessed on 13/07/2026
14. New India Samachar Stable URL [https://newindiasamachar .pib.gov.in](https://newindiasamachar.pib.gov.in) › story › Feb Accessed on 15/07/2026
15. https://en.wikipedia.org/wiki/Member_states_of_BRICS Accessed on 18/07/2026
16. New India Samachar Stable URL [https://new indiasamachar.pib.gov.in](https://newindiasamachar.pib.gov.in) › story › Feb Accessed on 22/07/2026
17. Ministry of External Affairs, Stable URL <https://www.mea.gov.in/bilateral-documents?dtl/41144> access on 29/07/2026

18. Pant Harsh V. ,Observer Research Foundation. Stable URL <https://www.orfonline.org/hindi/research/glimpse-of-super-powers-in-brics-will-global-coefficients-change> Accessed on 02/08/2026
19. <https://navbharattimes.indiatimes.com/india/putin-xi-xi-jinping-and-narendra-modi-together-at-brics-will-india-become-the-center-of-global-power-balance/articleshow/131544186.cms> Accessed on 05/08/2026

